

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 25 मई, 2023 DATED-----

सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

एलजी को दी गई **शक्तियों** का दिल्ली सरकार ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एलजी को यमुना पर बनी उच्च-स्तरीय समिति का बतौर अध्यक्ष नियुक्त करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है। गत नौ जनवरी के अपने आदेश के जरिये एनजीटी ने यमुना नदी प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में विभिन्न अथॉरिटीज वाली इस कमेटी का गठन करते हुए एलजी को इसका अध्यक्ष बनाया है। सरकार के अनुसार एलजी दिल्ली के मात्र औपचारिक प्रमुख भर हैं।

दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार यमुना के प्रदूषण को दूर करने और उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन एनजीटी के आदेश के जरिये एलजी को दी गई कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताती है। एलजी को दी गई शक्तियां विशेष रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण करती हैं। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे और संविधान के अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों के अनुसार भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर एलजी नाममात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और वे

- कहा, एलजी को यमुना की उच्च स्तरीय कमेटी का चेयरमैन बनाना संविधान पीठ के आदेश की अवहेलना
- दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य



कमेटी में शामिल हैं इन विभागों के प्रतिनिधि

इस कमेटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, कृषि और वित्त विभागों के सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, वन महानिदेशक या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से उनके नामिती, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) या एमओईएफ और सीसी के एक प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दिल्ली सरकार ने एक समन्वित दृष्टिकोण को महत्व देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि एनजीटी के आदेश में इस्तेमाल की गई भाषा निर्वाचित सरकार को दरकिनार करती है। दलील दी

जनता की चुनी सरकार को कमजोर किया जा रहा

याचिका में यह दलील दी गई है कि एक ऐसा प्रशासनिक व्यक्ति जिसके पास संवैधानिक जनादेश नहीं है उसे कार्यकारी शक्तियां देना, असल में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र को कमजोर करता है। संविधान के अनुसार एलजी पूरी तरह से सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्य (एनसीटी आफ दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) के मामले में अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों पर कार्यकारी शक्तियां का विशेष अधिकार है। चार जुलाई, 2018 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 284.17 में कहा गया है कि अनुच्छेद 239-ए (4) में लिखे हुए "सहायता और सलाह" का अर्थ यह माना जाना चाहिए कि एनसीटी के एलजी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं।

गई है कि एक ऐसे प्राधिकरण को कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनके पास उन शक्तियों को रखने के संवैधानिक अधिकार का अभाव है और यह चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र को भी कमजोर करता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, MAY 25, 2023

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, MAY 25, 2023

13 plants to be checked for capacity, output for treating industrial effluents

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 24

DELHI LIEUTENANT Governor VK Saxena has directed an assessment to be carried out of the Common Effluent Treatment Plants (CETPs) in the city to determine their capacity and output with regard to treating industrial effluent.

Delhi has 13 CETPs for the treatment of industrial effluents. Saxena chaired a meeting recently, with representatives of the CETPs, the Chief Secretary and other officials, to review the functioning of the plants.

According to a communication from the L-G's office, Saxena was told that the CETPs are functioning at 68-70% of their capacity and many of them require upgradation. The communication added that out of 40,805 industrial units "and other such establishments" in the city, only 64% or 26,077 units were connected to CETPs, which means that 23,149, or 36% of these units were discharging industrial effluents "directly into the Yamuna".

Saxena, according to the communication, has described this as "criminal negligence" on the part of the industry associations and the government.

He has directed that an assessment of the plants, their capacity and output, be done in 30 days by a team of officers and representatives of CETPs to carry out the assessment.

At the meeting, Saxena was also told that CETPs are discharging treated effluent into the Najafgarh drain. This results in the treated effluents getting polluted again before they reach the Yamuna. To deal with this, he has directed the Delhi Development Authority (DDA), Municipal Corporation of Delhi (MCD), and Delhi Jal Board (DJB) to identify water bodies into which the treated effluent can be discharged instead of releasing it into the Najafgarh drain.

VSPA नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली

कस्ट्रक्शन साइटों पर मिले डेगू के मच्छर, कटे चालान

■ विस, ईस्ट दिल्ली: शाहदरा साउथ जोन में जगह-जगह कस्ट्रक्शन साइटों पर डेगू के मच्छर पाए गए। एमसीडी शाहदरा साउथ जोन के हेल्थ विभाग ने ऐसी सभी साइटों के 10,000-10,000 रुपये के चालान काटे। हेल्थ विभाग ने 14 मार्च 2023 से लेकर 18 मई 2023 तक 21 साइटों के चालान काटे।

इस समय शाहदरा साउथ जोन के तहत आने वाले प्रीत विहार वॉर्ड में सबसे अधिक कस्ट्रक्शन चल रहा है। किसी भी कस्ट्रक्शन साइट पर डेगू के मच्छरों की रोकथाम के लिए

किसी तरह का कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया। हेल्थ विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 10,000 रुपये के चालान काटे

से लेकर अब तक 21 कस्ट्रक्शन साइटों के चालान काटे। इनमें से 12 कस्ट्रक्शन साइटें प्रीत विहार वॉर्ड के तहत आती हैं। दूसरे नंबर पर आनंद विहार वॉर्ड के तहत आने वाली कॉलोनियां हैं। इस वॉर्ड में अलग-अलग पॉश कॉलोनी में पांच कस्ट्रक्शन साइटों के चालान काटे गए। खिचड़ीपुर में चल रहे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल की कस्ट्रक्शन साइट, कोडली स्थित पीडब्ल्यूडी की साइट और लक्ष्मी नगर स्थित डीडीए ऑफिस में भी डेगू के मच्छर पाए गए। शाहदरा साउथ जोन के डीएचओ डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Untreated effluents in river: Saxena sets deadline to find fix

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Effluents from around 36% industrial units in Delhi are discharged directly into the Yamuna without treatment as they are still not connected with the common effluent treatment plants (CETPs), Lt Governor VK Saxena was informed at an assessment meeting.

Lt Governor Saxena later called the behaviour of the industrial unit owners and the state government "criminal negligence."

The meeting, chaired by the LG, was recently held with the aim of stopping industrial effluents from entering the river and to review the status of the common effluent treatment plants (CETPs) in industrial areas of the capital.

The meeting was held with the officials managing all 13 common effluent treatment plants. The officials said that of the 40,805 industrial units in Delhi, 64% were enrolled as members of the CETPs, while 23,149 or 36% units were discharging industrial effluents directly into the river.

"The LG described this as criminal negligence on the part of the industry associations and the government," a statement from the LG's office said.

Saxena was told that the common effluent treatment plants were running at only 68-70% capacity and many plants needed an upgrade. For the last 10 years, no audit of the plants was done.

"The LG expressed concern that over 36% of industrial units were still not connected to CETPs and even amongst those which were members, 33 per cent were not paying membership charges," an official said.



VK Saxena

LG Saxena on Thursday set a 30-day deadline for officials to complete the assessment and directed officials in the meeting to constitute a team to get this task done.

"It also came out that due to the lack of any other alternative, where the treated water from CETPs could be discharged, the CETPs that were treating their effluents were discharging the same in the Najafgarh drain. This was resulting in the treated effluents again getting polluted before entering the Yamuna. The LG directed agencies like DDA, MCD and DJB to identify their respective water bodies, where the treated water from the CETPs could be discharged, rather than draining the same into the Najafgarh drain/the Yamuna," the LG's office said in the statement.

Karol Bagh stretch no longer a pedestrian haven, chaos is back

Paras Singh

paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: Karol Bagh's Ajmal Khan Road is synonymous with readymade garment shops, and is packed with shoppers at all times of the day. In 2016, the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) proposed that Karol Bagh be made pedestrian-friendly, and as part of the project, the erstwhile North Delhi Municipal Corporation or North MCD suggested that Ajmal Khan road be treated along the lines of an open-air mall. In April 2019, it declared the entire 1.7km stretch a motorised vehicle free zone.

The curbs on vehicles did wonders — a localised study conducted by Centre for Science and Environment (CSE) on Ajmal Khan Road in May 2019 showed a 27% decrease in PM2.5 concentration in comparison to the nearby Arya Samaj Road. Similarly, noise levels were also found lower at Ajmal Khan Road compared to the roads nearby.

Soon, the North MCD began heralding Ajmal Khan Road as a rare success in civic body efforts to pedestrianise inner roads in the Capital. Cut to 2023, and the vehicle restrictions have all but disappeared. Both ends of the road have posters that clearly declare that the street is off limits for vehicles, with the legend "No entry, No parking" in bright, bold letters, but local residents, merchants and shoppers brazenly enter the street in their vehicles, and park there with impunity.

Footpaths have been encroached upon by shops and hawkers, and the little space left is usually where two-wheelers are parked. Pedestrians have nowhere to go but on the road itself, where they have to dodge cars — both moving and parked — even as two-wheelers drive with reckless abandon in an already crowded space.

The last vestige of the pedestrianisation initiative — planters placed along the road — have been converted into dustbins and spittle pails, while benches on pedestrian pathways have been roughly brushed aside to make space for cars to park.

Devinder Kohli, a trader in the market, said the project was bound to fail. "It is very difficult to



In April 2019, the 1.7km Ajmal Khan road was declared a motorised vehicle-free zone but vehicles still enter the stretch. (Below) The road went for redevelopment in May 2019. SANCHIT KHANNA/HT PHOTO, HT ARCHIVE



JUNE 2, 2019: HT reported that MCD pedestrianised Ajmal Khan Road. But the latest spot check found rampant violations

change habits. People don't want to carry expensive goods on foot, and then to an off-street parking site, due to safety issues. Nobody wants to pay ₹100 to park on nearby streets. They should have tried it (the pedestrianisation project) in a new market instead of a well-established one," he said.

The idea of pedestrianising Karol Bagh dates back to at least 2010, when the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning & Engineering) Centre or UTIPEC, which is the infrastructure planning arm of the DDA, approved a proposal by MCD to make the entire commercial centre vehicle-free, with off-street parking.

However, the plan was rolled back after stiff resistance from

market associations.

Later, in June 2016, MoHUA identified Karol Bagh for a model decongesting project. As part of this project, MCD began pedestrianising Ajmal Khan Road — the contract for on-street parking was cancelled, and bollards were installed at all intersections to cordon off vehicular traffic. Potted plants were placed on the road, street furniture and benches were provided at strategic locations, and dustbins were installed at regular intervals. Electric shuttles — similar to those at the airport — were also introduced for shoppers to take them to-and-fro the off-street parking spaces.

Today, most of these interventions lie in a dilapidated state. During spot checks on May 9 and

19, HT found that the valet parking service, which would park shoppers' vehicles at off-street sites, has been discontinued. The electric shuttles now only take shoppers to-and-fro the nearby Karol Bagh Metro station. The planters, meanwhile, are filled with trash while the dustbins themselves have all but disappeared.

Murli Mani, who heads the Vyapar Mandal Karol Bagh, placed the blame for the failure of the project squarely on the MCD. "They (the civic body) demanded that the MCD be paid ₹4.4 lakh per month for off-street parking, which was not part of our original agreement. A proposed multi-storey parking structure at nearby Shastri Park is

stuck in legal issues. Traders then started parking their cars outside their shops. The benches, footpaths and other street furniture now need urgent repairs. MCD should also start putting up railings as many of these benches are damaged by vehicles. All the progress has been rolled back," he added.

Shoppers, too, bemoan the failure of the project. Reena Gupta, 42, a resident of Mayur Vihar who frequents the market, said the road felt much more secure during the pedestrianisation initiative. "One can walk in a much more carefree manner when there are no vehicles moving behind you. One also needs to be careful, as many incidents of chain snatching are being reported from the city. Earlier, the market was a much more controlled space," she said.

An MCD spokesperson said violations on the pedestrianised stretch will be looked into by the corporation. "We will try to create a more robust system to stop these violations. We will also examine what arrangements can be made with local traders' associations in terms of parking management, and if something can be done on a revenue sharing basis, similar to that in Lajpat Nagar," the spokesperson said.

HT reached out to the Delhi Traffic Police, but officers refused to comment on the violation of the pedestrianisation project.

Road safety expert Sarika Panda Bhatt said pedestrianisation projects have the potential to greatly improve the liveability and sustainability of cities, so it is important to evaluate the reasons behind the failure of the Ajmal Khan Road project.

"The initial pedestrianisation of Ajmal Khan Road was a positive step, as it aimed to create a safer and more vibrant space for pedestrians... The return of vehicles to the pedestrianised area and the utilisation of the road width for car parking is concerning. It indicates a lack of sustained commitment to prioritising pedestrians and promoting sustainable modes of transportation. It is crucial to ensure that once pedestrianisation initiatives are implemented, they are consistently enforced and monitored to prevent such relapses," she said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, MAY 25, 2023

NAME OF NEWSPAPERS-----

-----DATED-----

DJB plans 200 tubewells by Aug to ramp up water output

Siddhanta Mishra
@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Jal Board (DJB) plans to start around 200 tubewells by August as the no-objection certificate from land owning agencies in different departments has come, officials said.

The DJB has been working on planning 500 tubewells around wastewater treatment plants and lakes and other areas to increase water capacity in the city.

"For now, we have permission for 200 tubewells on land owned by the DDA, PWD and forest department, Gram Sabha and irrigation department. So, we have started working in these areas and are confident of drawing water by July-August," a DJB official said.

As direct groundwater has a natural hardness to it, so reverse osmosis (RO) plants will also be installed along with the tubewells to reduce the hardness.

"The work will be done in six

DJB OFFICIAL SAYS

The work will be done in six phases to increase the total water production in the city by around 45 MGD

phases to increase the total water production in the city by around 45 MGD," the official said.

The DJB has decided to set up RO plants with tubewells in unauthorised colonies and water-scarce areas, where water is not supplied through a pipeline but by tankers. Areas like Sarita Vihar, Bawana, Sonia Vihar are a part of this plan where the DJB has started work on priority to increase water production.

As the summer approaches, water problems increase every year. There is a requirement of around 1,650 million gallons per day (MGD) of drinking water in the city, but department

produces 980-1,000 MGD.

By increasing the number of tubewells along artificial lakes, the DJB hopes to increase water production capacity, said official.

In February, chief minister Arvind Kejriwal held a high-level meeting and instructed officials to assess the water coming out of tubewells every day. He directed the officials to submit two to three designs for setting up 1,000 RO plants in unauthorised colonies in North East Delhi.

The work of around 300 tubewells was stuck due to land availability problems.

The CM also asked officials to establish some coordination with departments and identify land as soon as possible so that work could be started quickly.

Officials said that a joint inspection was done to find locations and applications were made to the district administration, the departments concerned and the DDA for plots.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

 the pioneer

NEW DELHI | THURSDAY | MAY 25, 2023

DATED

Delhi plea in SC against NGT decision to appoint LG as Yamuna panel head

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Government has filed a petition in the Supreme Court challenging the National Green Tribunal's decision to appoint the Lieutenant Governor (LG) as the Chairman of the High-Level Committee on Yamuna. The Delhi Government has urged the top court that the NGT order violates the Constitutional scheme of governance in Delhi as well as the 2018 and 2023 orders of the Constitution Bench of the Supreme Court.

Through its order dated 9.01.2023, the NGT had established this committee, comprising various authorities in Delhi, to address the issue of Yamuna River pollution, with the LG, a mere figurehead of the state, as its Chairman.

"In its petition, the Delhi Government has recognised the need for interdepartmental coordination to address Yamuna's pollution and implement remedial measures, but it has strongly objected to the executive powers granted to the LG through the NGT's order. These powers encroach upon areas exclusively under the competence of the elected government of Delhi," the AAP government said in a statement.

In its appeal, the Delhi Government contended that according to the administrative structure in Delhi and the provisions of Article 239AA of the Constitution, the LG serves as a nominal figurehead, except in matters pertaining to land, public order, and police, where the LG exercises powers delegated by the Constitution. The Delhi government acknowledged the



importance of a coordinated approach, but it asserted that the language used in the NGT order sidelines the elected government. The plea explains that granting executive powers to an authority that lacks the constitutional mandate to possess them undermines the elected government's rightful jurisdiction.

"The Delhi Government further contended that the NGT's proposed remedial measures, such as utilising treated water for agriculture, horticulture, or industrial purposes, preventing waste discharge and dumping, protecting floodplain zones, maintaining dredging flow, implementing plantations, and desilting drains, require budgetary allocations that are approved by the legislative assembly," it said.

Consequently, the role of the elected government becomes crucial in overseeing these measures. The appeal points out that the elected government is committed to addressing the issue of making Yamuna

a clean river free from pollutants and allocating the necessary funds. However, the current scheme outlined in the NGT order establishes a committee led by an unelected figurehead, sidelining the elected and accountable government of NCTD. While an inter-agency committee is desirable for coordination purposes, it should be overseen by the elected head of government, the Chief Minister in this case, the plea says.

The committee includes the Chief Secretary of Delhi, Secretaries of the Irrigation, Forest and Environment, Agriculture, and Finance Departments of the Delhi Government, the Chief Executive Officer of Delhi Jal Board, the Vice Chairman of the Delhi Development Authority, a representative from the Ministry of Agriculture, Government of India, the Director-General of Forests or his nominee from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), a representative from the Ministry of Jal Shakti (MoJS) or MoEF & CC, the Director-General of the National Mission for Clean Ganga (NMCG), and the Chairman of the Central Pollution Control Board (CPCB).

The Delhi Government also highlighted that a Constitution Bench of the Supreme Court, in its judgement in the case of State (NCT of Delhi) v. Union of India (2018) 8 SCC 501, established that the elected government of NCT of Delhi possesses exclusive executive powers over all subjects in the State and Concurrent List, with the exception of "public order," "police," and "land."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

NAME OF NEWSPAPER NEW DELHI | THURSDAY | MAY 25, 2023

BJP's outreach prog on Centre's role in development soon EAM Jaishankar, former Gujarat CM Rupani to supervise month-long campaign

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The BJP will conduct a month-long outreach programme in Delhi, highlighting the Narendra Modi Government's contribution to the growth of infrastructure in transport, health and the social sector in the national Capital. The outreach programme will be supervised by External Affairs Minister S Jaishankar and former Gujarat chief minister Vijay Rupani.

The Modi government has developed Delhi in every field, including education, health, transport, road infrastructure, pollution control and public welfare, among others, at the cost of lakhs of crores of rupees, the BJP's Delhi unit chief Virendra Sachdeva said at a joint press conference. "When we pass through the Kartavya Path of New Delhi, we realise our duties towards the country," Sachdeva said, listing various

works done by the BJP-led Centre.

Highlighting the Modi government's achievements, Delhi BJP president said in the last 9 years, the Modi government has approved about 20 Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas for Delhi, apart from the special hospitals built during the Covid period has expanded hospitals like AIIMS, Safdarjung, R.M. Lohia, FAME scheme electric buses plying on the roads of Delhi, expansion of the fourth phase of Metro, cleaning of mountains of garbage to reducing Delhi's air pollution, construction of Third Ring Road in Delhi, Pragati Maidan Tunnel, Dhaulakuan, Mahipalpur, Meerut Expressway, Eastern-Western Peripheral Road are rejuvenating not only Delhi but the entire NCR.

The campaign to raise awareness about what the Modi



government has done for the people of Delhi in its nine years will commence on May 30. Rupani and Jaishankar will supervise the campaign in the city's seven Lok Sabha constituencies, party leaders said.

Leader of Opposition in Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri said he has not witnessed any other central government undertake so many works in Delhi as done by the Modi government in its nine years.

Bidhuri claimed that in the current financial year alone, the Modi government has spent ₹60,000 crore for the development of highways in and around Delhi, ₹8,000 crore on hospitals, ₹10,355 crore on the Delhi Police, ₹7,643 crore on the Delhi Development Authority, ₹4,743 crore on the New Delhi Municipal Council, ₹13,000 crore on the expansion of the Delhi Metro and ₹3,000 crores on other heads. All these projects combined totalled a

whopping ₹1.5 lakh crore. He said that along with the regularization of unauthorized colonies in Delhi, the Modi government brought happiness in the lives of common citizens by starting the registry registration process of houses in these colonies.

Bidhuri, while keeping the 29 point list of development work point said he feel proud and he believe that today every citizen of Delhi is proud of his or her decision to elect Modi government in 2014 and 2019. The BJP leaders cited various completed and upcoming projects, including the eastern and western peripheral expressways, the Pragati Maidan tunnel, ring road and highway projects, the Regional Rapid Transport System, the National War Memorial, Bharat Vandana Park and the India International Convention and Expo Centre, among others, as achievements of the Modi government.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPER: NEW DELHI | THURSDAY, 25 MAY, 2023 ED: _____

AMID A LINGERING CONFLICT BETWEEN CENTRE AND AAP GOVT

Delhi govt moves SC against NGT order naming L-G as chief of HLC on Yamuna

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi government has moved the Supreme Court against an order of the National Green Tribunal naming Lieutenant Governor V K Saxena as the chairperson of the High-Level Committee (HLC) on Yamuna, amid a lingering conflict between the Centre and the national Capital's AAP dispensation.

Noting that substantial work remains unexecuted for the rejuvenation of river Yamuna, the NGT had formed a High-Level Committee and requested the lieutenant governor of Delhi to head the committee.

Contending that the L-G is only a "figurehead" except for three subjects- police, public order and land — the plea before the top court has sought directions to set aside the NGT's order.

Referring to the recent judgement of the top court on the administrative services row between the Centre and the Delhi government, the plea stated the effect of the NGT's orders cannot be to confer executive



utive powers on an authority that cannot, under the constitutional scheme, be conferred on it and is instead vested with the elected government.

"It is submitted that the issues concerning the present appeal are within the domain of the legislative powers conferred upon the Legislative Assembly and do not fall within any exception as laid down in the Constitution.

"In light of the above-settled position of law, affirmed most recently by this Court in Civil Appeal 2357 of 2017, the order of NGT is legally not tenable," the petition said.

It said remedial steps as suggested by the NGT such as using treated water for agriculture, horticulture or industrial purposes, preventing discharge/dumping of any waste, protecting of flood plain zones, etc are all which require budgetary allocations that are cleared by the legislative assembly and so the role of the elected government becomes extremely necessary.

"The elected government is keen to work on the issue of making Yamuna a clean river free from any kind of pollutants and to allocate the necessary funds, however, the present scheme under the impugned

Highlights

- » Noting that substantial work remains unexecuted for the rejuvenation of river Yamuna, the NGT had formed a High-Level Committee and requested the lieutenant governor of Delhi to head the committee
- » Contending that the L-G

is only a "figurehead" except for three subjects- police, public order and land — the plea before the top court has sought directions to set aside the NGT's order

- » Referring to the recent judgement of the top court on the administrative services

row between the Centre and the Delhi government, the plea stated the effect of the NGT's orders cannot be to confer executive powers on an authority that cannot, under the constitutional scheme, be conferred on it and is instead vested with the elected government

order sets up a committee headed by an unelected figurehead and side-lines the elected and popularly accountable government of the NCTD," the plea said.

"While the appellant acknowledges the need for inter-departmental coordination and cooperation to ensure the cleaning of the Yamuna and for remedial measures in that regard, the appellant is aggrieved by the executive powers conferred on the Lt. Governor vide the impugned order over areas in which only the elected government of the NCT of Delhi enjoys competence," it said.

In its order, the NGT had said there is still a huge gap between the generation of sewage and available treatment facilities.

"The estimated gap is said to be 194.5 million gallons per day (MGD) of sewage, interception and diversion of about 147 drains (connected to Najafgarh and Shahdara drains) and other small drains joining bigger drains remains (pending) and wastewater from 1,799 unauthorized colonies and 630 JJ clusters is reportedly going into the Yamuna," the NGT had said.

The green panel had said there was a need to plant trees

on the flood plains of the river and buffer zones of the drains, besides undertaking engineering, structural and biological measures for a comprehensive catchment area treatment plan.

Other committee members would include the chief secretary, secretaries of various Delhi government departments, CEO of Delhi Jal Board, DDA officials, top officials of the Union ministries of Agriculture, Jal Shakti and Environment, chairman of the Central Pollution Control Board and director general of National Mission for Clean Ganga (NMCG).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

THURSDAY, 25 MAY, 2023 | NEW DELHI

NAME OF NEWSPAPERS---

In a first, L-G chairs meeting to review status of CETPs

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: Concerned with the untreated industrial effluent flowing into the Yamuna, Delhi L-G, VK Saxena, in a first, chaired a meeting to review the status of the Common Effluent Treatment Plants (CETPs) functioning in the industrial areas of the national Capital.

The meeting sought to assess the role of CETPs in mitigating pollution in the Yamuna. It was brought to the notice of L-G that CETPs were running at only 68-70 per cent of their capacity and many plants required up-gradation. It was also informed that for the last 10 years no audit of the plants had been undertaken.

Of the 40,805 industrial units and other such establishments in the city, only 64 per cent, i.e. 26,077 were connected to CETPs for treatment of effluent generated by them, as a result of which 23,149 i.e. 36 per cent units were discharging industrial effluent directly into the Yamuna. The L-G described



It was brought to the notice of L-G that CETPs were running at only 68-70% of their capacity and many plants required up-gradation

this as criminal negligence on part of the Industry Associations and the government.

The L-G expressed deep concern over the fact that there are still 36 per cent of industrial units who were not connected to CETPs and even amongst those who were members, 33 per cent were not paying membership charges, resulting in unmiti-

gated pollution into the river.

The L-G set a deadline of 30 days to complete the assessment and directed officials present in the meeting to constitute a team comprising officers and representatives of the CETPs to get this task done.

It also came out that due to lack of any other alternative, where the treated water from CETPs could be discharged, CETPs that were treating their effluent were discharging the same in the Najafgarh drain. This was resulting in treated effluent again getting polluted before entering the Yamuna. The L-G directed agencies like DDA, MCD and DJB to identify their respective water bodies, where the treated water from the CETPs could be discharged, rather than draining the same into the Najafgarh drain/the Yamuna.

The L-G assured the CETPs that all such matters will be suitably addressed and taken up once the assessment of the installed capacity of the CETPs is completed in the next 30 days.

पंजाब केसरी
DELHI

एलजी की यमुना समिति अध्यक्ष नियुक्ति को सुप्रीम चुनौती

पंजाब केसरी/नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल (एलजी) को यमुना पर बनी उच्च-स्तरीय समिति का बतौर अध्यक्ष नियुक्त करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है। 09 जनवरी 2023 के अपने आदेश के जरिए एनजीटी ने यमुना नदी प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में विभिन्न अर्थातिजीव वाली इस कमेटी का गठन करते हुए एलजी को इसका अध्यक्ष बनाया है। जबकि एलजी दिल्ली के मात्र औपचारिक प्रमुख भर हैं। इस कमेटी में दिल्ली

● दिल्ली सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट अब एनजीटी का आदेश रद्द कर दे



के मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, कृषि और वित्त विभागों के सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, वन महानिदेशक या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से उनके नामित, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) या एमओईएफ और सीसी के एक प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

संजय सिंह के सहयोगियों पर ईडी की छापेमारी

ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं सांसद संजय सिंह के कुछ सहयोगियों के परिसरों सहित कई ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। 'आप' नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि उनके दो सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के परिसरों पर संघीय एजेंसी छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि करीब छह स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है।



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-

अमर उजाला

DATED-

गुरुवार, 25 मई 2023

36 फीसदी उद्योग बगैर उपचारित पानी कर रहे यमुना में प्रवाहित

पूरी क्षमता से नहीं चल रहे सीईटीपी, एलजी ने 30 दिन में क्षमता के आकलन के दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। यमुना में अनुपचारित औद्योगिक प्रवाह से चिंतित दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में सामान्य बहिष्काव उपचार संयंत्रों (कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट-सीईटीपी) की स्थिति की समीक्षा के लिए हाल ही में बैठक हुई।

इसमें यमुना में प्रदूषण कम करने में सीईटीपी की भूमिका और पूर्ण क्षमता और मौजूदा अंतर का 30 दिन के अंदर आकलन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में 13 सीईटीपी से संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी सहित मुख्य सचिव भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान एलजी के ध्यान में लाया गया कि सभी सीईटीपी अपनी क्षमता के केवल 68-70 प्रतिशत पर ही चल रहे थे, जबकि कई संयंत्रों को अपग्रेड किया जाना जरूरी है। यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों से संयंत्रों का कोई ऑडिट नहीं किया गया था। 40805 औद्योगिक इकाइयों और दूसरे प्रतिष्ठानों में से केवल 64 प्रतिशत



संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारियों संग बैठक करते एलजी। अमर उजाला

सीईटीपी के हालात की समीक्षा की उपराज्यपाल ने

(26077) ही सीईटीपी से जुड़े थे। 36 फीसदी यानी 23149 औद्योगिक इकाइयों से उपचार के बगैर ही प्रवाह को यमुना में प्रवाहित किया जा रहा है। एलजी ने इसे औद्योगिक संगठनों और सरकार की घोर लापरवाही के साथ-साथ आपराधिक बताया था।

उन्होंने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि अभी भी 36

फीसदी औद्योगिक इकाइयां सीईटीपी से जुड़ी नहीं थीं, जबकि 33 प्रतिशत ने सदस्यता शुल्क का भी भुगतान नहीं किया। इससे यमुना में प्रदूषण बढ़कर असंतुलित हो गया। एलजी के निर्देश पर सभी पहलुओं का गहनता से मूल्यांकन करना जरूरी है। उपराज्यपाल ने मूल्यांकन का काम पूरा करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है।

बैठक में यह भी सामने आया कि कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से उपचार के बाद सीईटीपी से नजफगढ़ नाले में ही पानी को छोड़ा जा रहा था। नतीजतन

प्रतिनिधियों ने कहा रखरखाव और संचालन के लिए राशि कम

सीईटीपी के प्रतिनिधियों ने एलजी के संज्ञान में लाया कि 2 नवंबर, 2022 की अधिसूचना के मुताबिक उद्योग विभाग की तरफ से अलग-अलग श्रेणी के उद्योगों (लाल, नारंगी और सफेद) में वर्गीकृत किया गया। इसके लिए तय राशि को कम बताते हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि इसके संचालन और रखरखाव की लागत अधिक है। एलजी ने सीईटीपी को आश्वासन दिया कि ऐसे सभी मामलों का उचित समाधान किया जाएगा। 30 दिन के अंदर मूल्यांकन होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

उपचारित प्रवाह दोबारा प्रदूषित हो रहा था। एलजी ने डीडीए, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को संबंधित जल निकायों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद नजफगढ़ नाले में प्रवाहित करने के बजाय उपचारित पानी को यमुना में प्रवेश करने की इजाजत देने के निर्देश दिए थे।